स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर

(मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर, उ0प्र0, पिन–242226)
Website- ssuniversity.ac.in
E-mail ID – registrarssu26@gmail.com

पत्रांक : 38 /Reg.off./SSU/2026-27 दिनांक: 07.10.2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषयः मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.- 132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग – 1, उ०प्र० शासन के संलग्न पत्र संख्या–1528/सत्तर–1–2026, दिनांक 05 अक्टूबर, 2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली उपर्युक्त विषयक योजित याचिका में पारित आदेश दिनांक 20.08.2026 के क्रम में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के परिसर में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करते हुये अनिवार्य दहेज विरोधी कार्यशालायें, कानूनी अधिकार सेमीनार और छात्रों के नेतृत्व में जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संलग्न पत्र में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के परिसर में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करते हुये अनिवार्य दहेज विरोधी कार्यशालायें, कानूनी अधिकार सेमीनार और छात्रों के नेतृत्व में जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 1, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली मण्डल, बरेली।
3. कुलपति कार्यालय, स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1528/सत्तर-1-2026-

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा
उ0प्र0 , प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त निजी/राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक: 05 सितम्बर, 2026**

विषयः- मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. के संबध में। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (पुलिस) अनुभाग-15 के पत्र संख्या-332/ई-1474955/2026 दिनांक 23 सितम्बर, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2026 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उपरोक्त Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2026 में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित दिये गये आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् हैः-

"3. Having considered the material placed before us and the submissions advanced, we now proceed to pass the following directions:

i.....

ii. **Awareness and Educational Measures:** States and Union Territories, in coordination with Departments of Education, Women and Child Development Departments, State Legal Services Authorities and other appropriate bodies, shall undertake sustained awareness and sensitization programmes concerning:

a. the social evil of dowry,

b. gender equality,

c. constitutional values,

d. and women's rights, including through educational curricula, awareness campaigns, community outreach programmes and legal literacy initiatives.

3- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 के अनुपालन हेतु शासनादेश संख्या:-1270/सत्तर-1-2026 दिनांक 18 जुलाई, 2026 के माध्यम से विश्वविद्यालयों/ महाविद्यलायों के परिसर में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करते हुए अनिवार्य दहेज-विरोधी कार्यशालाएं, कानूनी-अधिकार सेमिनार और छात्रों के नेतृत्व में जागरूकता अभियान आयोजित करने निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2026 के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

Digitally signed by
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव
Date: 05-09-2026 14:41:11

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-15 को उनके उक्त पत्र दिनांक 23.09.2026 के संदर्भ में ।
3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

Digitally signed by
SANJAY KUMAR DWIVEDI
Date: 05-10-2026 15:30:24

(**संजय कुमार द्विवेदी**)
उप सचिव

फैक्स / अतिमहत्वपूर्ण

संख्या- 332/I/1474955/2026/

ई-मेल आई.डी.- shome.p15@up.gov.in

प्रेषक,

सतीश पाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

91/PSNEW/2026
25.09.2026

(सुनील कुमार)
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-15 **लखनऊः दिनाँक- 23-09-2026**

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण आवेदन संख्या 2689-90/2025 (दाण्डिक अपील संख्या 132-133/2017, उ0प्र0 राज्य बनाम अजमल बेग) में दिनांक 20.08.2026 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री सुदीप कुमार (ए0ओ0आर0), मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, स्थायी अधिवक्ता, उ0प्र0 राज्य के पत्र दिनांक 16.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Misc. Application Nos. 2689-90 of 2025 in Crl. Appeal Nos. 132-133 of 2017 (The State of Uttar Pradesh Vs. Ajmal Beg Etc.) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली रिपोर्ट (compliance-cum-periodic reports) के साथ दिनांक 20.08.2026 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अगली सुनवाई दिनांक 15.10.2026 से पूर्व अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2026 द्वारा विस्तृत निर्देश समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा उच्च न्यायालयों हेतु पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं:-

"3. Having considered the material placed before us and the submissions advanced, we now proceed to pass the following directions:

i. **Strengthening of Institutional Support Mechanisms:** States and Union Territories shall ensure effective functioning and

39 सं/19 (D)
SO-I
25.9.2026

dissemination of information regarding Dowry Prohibition Officers appointed/ designated under the Dowry Prohibition Act, 1961, and shall strengthen:

a. One Stop Centres,

b. Family Counselling Centres,

c. Women Help Desks,

d. victim assistance mechanisms,

e. helplines, and

f. online grievance redressal systems for facilitating access to support and legal remedies for aggrieved women.

ii. **Awareness and Educational Measures:** States and Union Territories, in coordination with Departments of Education, Women and Child Development Departments, State Legal Services Authorities and other appropriate bodies, shall undertake sustained awareness and sensitization programmes concerning:

a. the social evil of dowry,

b. gender equality,

c. constitutional values,

d. and women's rights, including through educational curricula, awareness campaigns, community outreach programmes and legal literacy initiatives.

iii. **Priority Classification and Monitoring of Cases:** All Courts dealing with offences under Sections 304B and 498A IPC/Sections 80 and 85 BNS, 2023 shall, as far as practicable, treat such matters as priority cases and endeavour to ensure expeditious disposal thereof, without adversely affecting the hearing of other categories of cases. The concerned District Judiciary shall identify cases pending beyond three years, particularly those pending at the stage of framing of charge or recording of evidence, and undertake periodic monitoring thereof through monthly or quarterly review mechanisms.

iv. **Time-Bound Progression of Trial:** All Trial Courts shall endeavour, as far as practicable and subject to compliance with statutory safeguards under the CrPC/BNSS, to:

shall endeavour to integrate, within the existing Courts Dashboards/CIS infrastructure:

a. stage-wise pendency tracking,

b. digital dashboards,

c. automated alerts for old pending matters,

d. and case monitoring systems in respect of cases arising under Sections 304B and 498A IPC/Sections 80 and 85 BNS.

vii. Review of Pending Matters Before High Courts: All High Courts shall endeavour to periodically review old pending criminal appeals, revisions, petitions under Section 482 CrPC/Section 528 BNSS, 2023 and bail matters, particularly matters involving interim stay of trial proceedings, and take appropriate steps for their expeditious listing and disposal. Wherever proceedings are stayed, such orders may be periodically reviewed in accordance with law.

viii. Training, Sensitization and Specialized Prosecution: All States/ Union Territories and Hon'ble High Courts shall ensure periodic training and sensitization programmes for:

a. Judicial Officers.

b. Police Officials,

c. Prosecutors,

d. Protection Officers,

e. Counsellors, and

f. Other stakeholders dealing with dowryrelated offences, through Judicial Academies, Police Training Institutions and other appropriate bodies.

States may also endeavour to designate prosecutors having experience and sensitization in offences against women for conducting prosecutions under Sections 304B and 498A IPC.

ix. Mediation/Counselling in Appropriate Matrimonial Disputes: In cases arising primarily out of matrimonial discord and not involving allegations of death, grievous physical violence, or other serious offences, the concerned Courts may, wherever permissible in law and considered appropriate, explore the possibility of mediation or counselling through duly

mediators/counsellors, without compromising the rights of parties or the seriousness of cognizable offences.

x. **Compliance and Periodic Reporting**: All High Courts and States/Union Territories shall file status/compliance reports on 15th of January, May and September before this Court for consideration and further directions, if any, until the pendency of cases under Sections 304B and 498A IPC/corresponding Sections 80 and 85 of BNS, 2023 and cases involving Dowry Prohibition Act 1961 is substantially reduced, indicating, inter alia, the following:

a. pendency and disposal statistics,

b. stage-wise status of cases,

c. awareness initiatives undertaken,

d. appointment/designation of Dowry Prohibition Officers,

e. training programmes conducted,

f. and measures adopted pursuant to the present directions.

4. List the cases with compliance-cum-periodic reports on 15th October, 2026.

5. We appreciate the efforts put in by Mr. Kunal Chatterji, learned counsel, and learned senior counsel/counsel appearing for the respective parties."

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2026 को पारित उक्त आदेश में दिये गये समस्त निर्देशों का अपने-अपने विभाग/कार्यालय के स्तर से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा तद्नुसार की गयी कार्यवाही का विवरण दर्शाते हुए अनुपालन आख्या अनिवार्य रूप से दिनांक 30.09.2026 तक गृह(पुलिस)अनुभाग-15 के ई-मेल आईडी shome.p15@up.gov.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे समस्त विभागों से प्राप्त आख्याओं को संकलित कर एक समेकित अनुपालन आख्या सुनवाई दिनांक-15.10.2026 के पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दाखिल करायी जा सके। प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशों से आच्छादित है। अतः सर्वोच्च प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
SATISH PAL
Date: 23-09-2026 19:50:07

(सतीश पाल)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. श्री सुदीप कुमार (ए0ओ0आर0), मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, स्थायी अधिवक्ता, उ0प्र0 राज्य के पत्र दिनांक 16.09.2026 के क्रम में।

आज्ञा से,

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

गृह विभाग पत्रांक- 332-6-30-15-2026

SUDEEP KUMAR

Advocate-on-Record
Supreme Court of India
Standing Counsel, State of Uttar Pradesh

1.0909/ACS(H)/WRIT/2026

Dated: 16/09/2026

आज प्राप्त
दिनांक 17-09-26 सचिव (ए० के०)

Most urgent/priority/

SEC(CA)(1) PHS

TO,
THE CHIEF SECRETARY
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
csup@nic.in

16/09/26
विशेष सचिव एवं स्थानक अधिकारी
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

SUB: LETTER FOR COMPLIANCE OF ORDER DATED 20.08.2026 PASSED IN M.A. NO. 2689 OF 2025 IN CRIMINAL APPEAL NO. 132 OF 2017 TITLED 'STATE OF U.P. VS. AJMAL BEG ETC.'REGARDING SUBMISSION OF PERIODIC REPORTS ON BHEALF OF THE STATE OF UTTAR PRADESH

1446
1SC(SP)

Respected Sir,

I would like to bring you kind attention on order dated **20.08.2026**, passed by the Hon'ble Apex Court, wherein Hon'ble Court has issued comprehensive directions. The operative directions of the Hon'ble Court are reproduced below for immediate reference:

09.2026
(निमिलेश कुमार)
अपर निजी सचिव
सचिव गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

"3. Having considered the material placed before us and the submissions advanced, we proceed to pass the following directions:

1/HCP/26
S(D)(SS)

i. **Strengthening of Institutional Support Mechanisms**: States and Union Territories shall ensure effective functioning and dissemination of information regarding Dowry Prohibition Officers appointed/designated under the Dowry Prohibition Act, 1961, and shall strengthen:

a. One Stop Centres,

b. Family Counselling Centres,

c. Women Help Desks,

1895

.09.2026
(सतीश माल)
विशेष सचिव
गृह विभाग,
उ०प्र० शासन।

Office: D-111, Defence Colony, Delhi-110024
Email: advsudeep1@gmail.com, Mob: 9871185301

d. victim assistance mechanisms,

e. helplines, and

f. online grievance redressal systems for facilitating access to support and legal remedies for aggrieved women.

ii. **Awareness and Educational Measures**: States and Union Territories, in coordination with Departments of Education, Women and Child Development Departments, State Legal Services Authorities and other appropriate bodies, shall undertake sustained awareness and sensitization programmes concerning

a. the social evil of dowry,

b. gender equality,

c. constitutional values,

d. and women's rights, including through educational curricula, awareness campaigns, community outreach programmes and legal literacy initiatives.

iii. **Priority Classification and Monitoring of Cases**: All Courts dealing with offences under Sections 304B and 498A IPC/Sections 80 and 85 BNS, 2023 shall, as far as practicable, treat such matters as priority cases and endeavour to ensure expeditious disposal thereof, without adversely affecting the hearing of other categories of cases. The concerned District Judiciary shall identify cases pending beyond three years, particularly those pending at the stage of framing of charge or recording of evidence, and undertake periodic monitoring thereof through monthly or quarterly review mechanisms.

iv. **Time-Bound Progression of Trial**: All Trial Courts shall endeavour, as far as practicable and subject to compliance with statutory safeguards under the Cr.P.C./BNSS, to:

a. secure prompt appearance of accused expeditiously after filing of charge-sheet;

b. consider framing of charge preferably within 60 to 90 days from filing of charge-sheet;

Office: D-111, Defence Colony, Delhi-110024
Email: advsudeep1@gmail.com, Mob: 9871185301

SUDEEP KUMAR
Advocate-on-Record
Supreme Court of India
Standing Counsel, State of Uttar Pradesh

c. commence recording of evidence within a reasonable period after framing of charge; and

d. proceed with recording of evidence on a continuous or day-to-day basis in terms of Section 309 CrPC/Section 346 BNSS, 2023.

Provided the timelines indicated herein may ordinarily be adhered to as directory benchmarks, subject to exceptional cases involving multiple accused, supplementary charge-sheets, forensic delays, non-availability of accused, or other reasons to be recorded.

v. Witness Regulation of Adjournments and Management/Witness Calendar:

a. Trial Courts/High Courts shall discourage unnecessary adjournments and ensure that adjournments are granted only upon recording reasons in writing. Where counsel for the accused repeatedly remains absent without sufficient cause, appropriate Legal Aid Counsel or Amicus Curiae may be appointed to ensure that proceedings are not unnecessarily delayed. Additionally, where the Investigating Officer has been transferred or retired, a substitute or holding officer shall be nominated sufficiently in advance to avoid adjournments.

b. Immediately after framing of charge, the Trial Court shall prepare a witness calendar indicating dates for examination of material witnesses, service of summons and sequencing of evidence. This will ensure structured witness management mechanisms, as far as practicable, to secure timely attendance of witnesses and avoid repeated deferment of evidence. Investigating Officers shall ensure prompt service of summons and production of witnesses.

vi. Use of Technology and Digital Monitoring: The High Courts shall endeavour to integrate within the existing Courts Dashboards/CIS infrastructure:

Office: D-111, Defence Colony, Delhi-110024
Email: advsudeep1@gmail.com, Mob: 9871185301

a. stage-wise pendency tracking,

b. digital dashboards,

c. automated alerts for old pending matters,

d. and case monitoring systems in respect of cases arising under Sections 304B and 498A IPC/Sections 80 and 85 BNS.

vii. Review of Pending Matters Before High Courts. All High Courts shall endeavour to periodically review old pending criminal appeals, revisions, petitions under Section 482 CrPC/Section 528 BNSS, 2023 and bail matters, particularly matters involving interim stay of trial proceedings, and take appropriate steps for their expeditious listing and disposal. Wherever proceedings are stayed, such orders may be periodically reviewed in accordance with law.

viii. Training, Sensitization and Specialized Prosecution: All States/Union Territories and Hon'ble High Courts shall ensure periodic training and sensitization programmes for:

a. Judicial Officers.

b. Police Officials,

c. Prosecutors,

d. Protection Officers,

e. Counsellors, and

f. Other stakeholders dealing with dowry-related offences, through Judicial Academies, Police Training Institutions and other appropriate bodies.

States may also endeavour to designate prosecutors having experience and sensitization in offences against women for conducting prosecutions under Sections 304B and 498A IPC.

ix. Mediation/Counselling in Appropriate Matrimonial Disputes: In cases arising primarily out of matrimonial discord and not involving allegations of death, grievous

Office: D-111, Defence Colony, Delhi-110024
Email: advsudeep1@gmail.com, Mob: 9871185301

SUDEEP KUMAR
Advocate-on-Record
Supreme Court of India
Standing Counsel, State of Uttar Pradesh

physical violence, or other serious offences, the concerned Courts may, wherever permissible in law and considered appropriate, explore the possibility of mediation or counselling through duly mediators/counsellors, without compromising the rights of parties or the seriousness of cognizable offences.

x. Compliance and Periodic Reporting: All High Courts and States/Union Territories shall file status/compliance reports on 15th of January, May and September before this Court for consideration and further directions, if any, until the pendency of cases under Sections 304B and 498A IPC/corresponding Sections 80 and 85 of BNS, 2023 and cases involving Dowry Prohibition Act 1961 is substantially reduced, indicating, inter alia, the following:

a. pendency and disposal statistics,

b. stage-wise status of cases,

c. awareness initiatives undertaken,

d. appointment/designation of Dowry Prohibition Officers,

e. training programmes conducted,

f. and measures adopted pursuant to the present directions.

4. List the cases with compliance-cum-periodic reports on 15th October, 2026."

(Copy of Order dated 20.08.2026 in M.A. No. 2689 of 2025 in Crl.A. No. 132 of 2017 is enclosed in pdf)

Therefore, it is requested you to kindly issue necessary directions for ensuring Compliance of order dated **20.08.2026** by filing Compliance cum Periodic Reports in a time bound manner before the Hon'ble Apex Court. **Next Date of hearing is on 15.10.2026.**

Kindly treat as Most Urgent.

Office: D-111, Defence Colony, Delhi-110024
Email: advsudeep1@gmail.com, Mob: 9871185301

Advocate-on-Record
Supreme Court of India
Standing Counsel, State of Uttar Pradesh

Thanking you,

Encl: As stated above:

[SUDEEP KUMAR]
Standing Counsel, State of U.P.

Copy to:

1. To,
   The Principal Secretary /Additional Secretary
   Department of Home,
   Government of U.P., Lucknow
   shome@nic.in

2. The Principal Secretary (Law) & L.R.,
   Government of Uttar Pradesh,
   Lucknow, Uttar Pradesh
   pslawupgov@gmail.com

3. The Addl. L.R/Special Secretary,
   Government of Uttar Pradesh,
   8-B, Tej Building, Bahadur Shah Zafar Marg,
   New Delhi.
   sclegalcell@gmail.com

Office: D-111, Defence Colony, Delhi-110024
Email: advsudeep1@gmail.com, Mob: 9871185301

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

MISC. APPLICATION NOS. 2689-90 OF 2025
IN
(CRL. APPEAL NOS. 132-133 OF 2017)

THE STATE OF UTTAR PRADESH ... **APPELLANT(S)**

VERSUS

AJMAL BEG ETC. ... **RESPONDENT(S)**

ORDER

1. This Court *vide* judgment dated 15.12.2025 passed in ***State of U.P. v. Ajmal Beg*** [Criminal Appeal Nos. 132-133 of 2017], while allowing the said appeals and restoring the judgment of trial court convicting the appellants under section 304-B and 498-A of the Indian Penal Code, 1860, (corresponding Sections 80 and 85 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) noted that while in this case,

Signature Not Verified
Digitally signed by NAVEEN D
Date: 2026.01.22 19:13:37 IST
Reason:

the accused person(s) has finally been brought to book, there are many cases in which it is not happen. Many who openly seek and give dowry go scot-free. It has been noted time and again, in various judicial pronouncements that Dowry Prohibition Act, 1961 suffers from various difficulties in its implementation. This Court further, acknowledged that when it comes to the giving and taking of dowry in particular, this practice unfortunately has deep roots in society, hence, it being not a matter of swift change, a concentrated effort is needed on the part of all the involved parties, be it Legislature, Judiciary, law enforcement agencies, civil society organizations etc. Therefore, to address the systemic delay and ineffective implementation attending prosecutions under Section 304-B and Section 498-A, IPC and the Dowry Prohibition Act, 1961 following directions were issued:

> "26. With an intent to further this change, we issue the following directions: -

(a) to ensure that the change brought in is able to make an impact on the efforts to eradicate this evil, it is to be ensured that the future generation, youngsters of today, are informed and made aware about this evil practice and the necessity to eschew it. As such, it is directed that States and even the Union Government consider changes as are necessary to the educational curricula across levels, reinforcing the constitutional position that parties to a marriage are equal to one another and one is not subservient to the other as is sought to be established by giving and taking of money and or articles at the time of marriage;

(b) The law provides for the appointment of Dowry Prohibition Officers40 in States. It is to be ensured that these officers are duly deputed, aware of their responsibilities and given the necessary wherewithal to carry out the duties entrusted to them. The contact details (name, official phone number and email ID) of such an officer designated to this position are disseminated adequately by the local authorities ensuring awareness of citizens of the area;

(c) the police officials, as also the judicial officers dealing with such cases, should periodically be given training, equipping them to fully appreciate the social and psychological implications which are often at the forefront of these cases. This would also ensure a sensitivity of the concerned officials towards genuine cases versus those which are frivolous and abusive of the process of law;

(d) it is not lost on us that the instant case began in 2001 and could only be concluded 24 years later by way of this judgment. It is but obvious that there would be many such similar cases. The High Courts are requested to take stock of the situation, ascertain the number of cases pending dealing with Section 304-B, 498-

A from the earliest to the latest for expeditious disposal and

(e) In furtherance of (a) above, we also recognize that many people today are/have been outside the education fold and that it is equally, if not more so, important to reach them and make accessible and comprehensible, the relevant information regarding the act of giving or taking of dowry as also other acts sometimes associated therewith, other times independent thereof (mental and physical cruelty) is an offence in law. The District Administration along with the District Legal Services Authorities, by engaging and involving civil society groups and dedicated social activists, is requested to conduct workshops/awareness programs at regular intervals. This is to ensure change at the grassroot level.

27. Let a copy of this judgment be circulated electronically to the Registrar General of the High Courts who are requested to place the same before the Learned Chief Justices and solicit directions in accordance with the above, and also, to the Chief Secretaries of all States for necessary follow up action.

27.1 While the main appeals are disposed of, so far as these directions are concerned, to ensure compliance thereof, as also issue any other directions as may be necessary, list this matter after four weeks. States are requested to file affidavits indicating the position qua the direction given under (b) hereinabove. The High Courts shall do the same for (d)."

2. Pursuant to the aforesaid directions, affidavits and data have been filed by several High Courts, States and Union Territories. We have heard the learned counsel appearing for the

States and, in particular, Mr. Kunal Chatterji, learned counsel, who has assisted this Court by placing on record a consolidated analysis of the affidavits/data so filed, along with suggestions received from the High Courts, States and Union Territories, and a set of proposed directions for the consideration of this Court.

3. Having considered the material placed before us and the submissions advanced, we now proceed to pass the following directions:

i. **Strengthening of Institutional Support Mechanisms:** States and Union Territories shall ensure effective functioning and dissemination of information regarding Dowry Prohibition Officers appointed/designated under the Dowry Prohibition Act, 1961, and shall strengthen:

   a. One Stop Centres,

   b. Family Counselling Centres,

   c. Women Help Desks,

d. victim assistance mechanisms;

e. helplines; and

f. online grievance redressal systems for facilitating access to support and legal remedies for aggrieved women.

ii. **Awareness and Educational Measures:** States and Union Territories, in coordination with Departments of Education, Women and Child Development Departments, State Legal Services Authorities and other appropriate bodies, shall undertake sustained awareness and sensitization programmes concerning:

a. the social evil of dowry,

b. gender equality,

c. constitutional values,

d. and women's rights, including through educational curricula, awareness campaigns, community outreach programmes and legal literacy initiatives.

iii. **Priority Classification and Monitoring of Cases:** All Courts dealing with offences

under Sections 304B and 498A IPC/Sections 80 and 85 BNS, 2023 shall, as far as practicable, treat such matters as priority cases and endeavour to ensure expeditious disposal thereof, without adversely affecting the hearing of other categories of cases. The concerned District Judiciary shall identify cases pending beyond three years, particularly those pending at the stage of framing of charge or recording of evidence, and undertake periodic monitoring thereof through monthly or quarterly review mechanisms.

iv. **Time-Bound Progression of Trial:** All Trial Courts shall endeavour, as far as practicable and subject to compliance with statutory safeguards under the CrPC/BNSS, to:

a. secure prompt appearance of accused expeditiously after filing of charge-sheet;

b. consider framing of charge preferably within 60 to 90 days from filing of charge-sheet;

c. commence recording of evidence within a reasonable period after framing of charge; and

d. proceed with recording of evidence on a continuous or day-to-day basis in terms of Section 309 CrPC/Section 346 BNSS, 2023.

Provided the timelines indicated herein may ordinarily be adhered to as directory benchmarks, subject to exceptional cases involving multiple accused, supplementary charge-sheets, forensic delays, non-availability of accused, or other reasons to be recorded.

v. **Witness Regulation of Adjournments and Management/Witness Calendar:**

a. Trial Courts/High Courts shall discourage unnecessary adjournments and ensure that adjournments are granted only upon recording reasons in writing. Where counsel for the accused repeatedly remains absent without sufficient cause, appropriate Legal Aid Counsel or Amicus Curiae may be

appointed to ensure that proceedings are not unnecessarily delayed. Additionally, where the Investigating Officer has been transferred or retired, a substitute or holding officer shall be nominated sufficiently in advance to avoid adjournments.

b. Immediately after framing of charge, the Trial Court shall prepare a witness calendar indicating dates for examination of material witnesses, service of summons and sequencing of evidence. This will ensure structured witness management mechanisms, as far as practicable, to secure timely attendance of witnesses and avoid repeated deferment of evidence. Investigating Officers shall ensure prompt service of summons and production of witnesses.

vi. **Use of Technology and Digital Monitoring:** The High Courts shall

endeavour to integrate, within the existing Courts Dashboards/CIS infrastructure:

a. stage-wise pendency tracking;

b. digital dashboards;

c. automated alerts for old pending matters;

d. and case monitoring systems in respect of cases arising under Sections 304B and 498A IPC/Sections 80 and 85 BNS.

vii. **Review of Pending Matters Before High Courts:** All High Courts shall endeavour to periodically review old pending criminal appeals, revisions, petitions under Section 482 CrPC/Section 528 BNSS, 2023 and bail matters, particularly matters involving interim stay of trial proceedings, and take appropriate steps for their expeditious listing and disposal. Wherever proceedings are stayed, such orders may be periodically reviewed in accordance with law.

viii. **Training, Sensitization and Specialized Prosecution:** All States/Union Territories

and Hon'ble High Courts shall ensure periodic training and sensitization programmes for:

a. Judicial Officers,

b. Police Officials,

c. Prosecutors,

d. Protection Officers,

e. Counsellors, and

f. Other stakeholders dealing with dowry-related offences, through Judicial Academies, Police Training Institutions and other appropriate bodies.

States may also endeavour to designate prosecutors having experience and sensitization in offences against women for conducting prosecutions under Sections 304B and 498A IPC.

ix. **Mediation/Counselling in Appropriate Matrimonial Disputes:** In cases arising primarily out of matrimonial discord and not involving allegations of death, grievous physical violence, or other serious offences,

the concerned Courts may, wherever permissible in law and considered appropriate, explore the possibility of mediation or counselling through duly trained mediators/counsellors, without compromising the rights of parties or the seriousness of cognizable offences.

x. **Compliance and Periodic Reporting:** All High Courts and States/Union Territories shall file status/compliance reports on 15th of January, May and September before this Court for consideration and further directions, if any, until the pendency of cases under Sections 304B and 498A IPC/corresponding Sections 80 and 85 of BNS, 2023 and cases involving Dowry Prohibition Act 1961 is substantially reduced, indicating, inter alia, the following:

a. pendency and disposal statistics,

b. stage-wise status of cases,

c. awareness initiatives undertaken,

d. appointment/designation of Dowry Prohibition Officers,

e. training programmes conducted,

f. and measures adopted pursuant to the present directions.

4. List the cases with compliance-cum-periodic reports on 15th October, 2026.

5. We appreciate the efforts put in by Mr. Kunal Chatterji, learned counsel, and learned senior counsel/counsel appearing for the respective parties.

.....J.
[SANJAY KAROL]

.....J.
[AUGUSTINE GEORGE MASIH]

NEW DELHI;
AUGUST 20, 2026.

SECTION II

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Miscellaneous Application Nos.2689-2690/2025 in Crl.A. Nos.132-133/2017

THE STATE OF UTTAR PRADESH PETITIONER(S)

VERSUS

AJMAL BEG ETC. RESPONDENT(S)

FOR ADMISSION

Date : 20-08-2026 These applications were called on for hearing today.

CORAM

HON'BLE MR. JUSTICE SANJAY KAROL
HON'BLE MR. JUSTICE AUGUSTINE GEORGE MASIH

For Petitioner(s) :Mr. Sharan Dev Singh Thakur, Sr. A.A.G.
Mr. Sudeep Kumar, AOR
Mr. Abhishek Saket, Adv.
Ms. Manisha, Adv.
Ms. Rupali, Adv.
Ms. Reya Paul, Adv.
Ms. Harshita Chawla, Adv.

Mr. Kunal Chatterji, AOR

For Respondent(s) :Mr. Shekhar Kumar, AOR
Mr. Shantanu Krishna, AOR

Mr. Varinder Kumar Sharma, AOR
Mr. Hit Lal, Adv.

Mr. Aravindh S., AOR
Mr. Aadithya Aravindh, Adv.
Ms. Anika Bansal, Adv.

Mr. Avneesh Arputham, AOR
Mr. Ankit Sharma, Adv.

Mr. Rajat Bhardwaj, A.A.G.
Ms. Baani Khanna, AOR
Mr. Robin Singh, Adv.
Mr. Kapil Balwani, Adv.
Ms. Komal Thakkar, Adv.

Ms. Tejal Tapaswini Nagauri, Adv.

Mr. P. I. Jose, AOR
Ms. P S Chandralekha, Adv.

Ms. Mrinmayee Sahu, Adv.
Ms. Mrinmayee Sahu, AOR
Mr. Sugam Kumar Jha, Adv.
Ms. Amruta Padhi, Adv.

Mr. Aljo K. Joseph, AOR
Mr. Sashwat Mishra, Adv.

Mr. Aaditya Aniruddha Pande, AOR
Mr. Siddharth Dharmadhikari, Adv.
Mr. Shrirang B. Varma, Adv.
Mr. Sourav Singh, Adv.
Ms. Chitransha Singh Sikarwar, Adv.

Mr. Bhuvan Kapoor, Adv.
Mr. Varun Chugh, Adv.
Mr. Krishna Kant Dubey, Adv.
Mr. Mukesh Kr. Verma, Adv.
Mr. Shashwat Parihar, Adv.
Mr. Yogesh Vats, Adv.
Mr. Shreekant Neelappa Terdal, AOR

Ms. G. Indira, AOR
Mr. Dinesh Kumar Mudgal, Adv.
Mr. Devendra Upadhayay, Adv.
Mr. Hitesh Kumar Sharma, Adv.
Mr. Anupam Kumar, Adv.
Mr. Akhileshwar Jha, Adv.
Mr. Avnish Kumar, Adv.

Mr. Sameer Abhyankar, AOR
Mr. Aryan Srivastava, Adv.
Mr. Krishna Rastogi, Adv.

Mr. Ankit Roy, AOR
Ms. Mrinalini Ramesh, Adv.
Ms. Jaya Pandey, Adv.

Mr. T. G. Narayanan Nair, AOR
Ms. Samyuktha H Nair, Adv.

Mr. Rahul Gupta, AOR

Mr. Anando Mukherjee, AOR
Mr. Shwetank Singh, Adv.
Mr. Utkarsh Anand, Adv.

Mr. Aman Choudhary, Adv.

Mr. Kunal Chatterji, AOR
Ms. Maitrayee Banerjee, Adv.
Mr. Rohit Bansal, Adv.
Mr. Varij Nayan Mishra, Adv.

Mr. Surjendu Sankar Das, AOR
Mr. Vishwajeet Singh Shekhawat, Adv.

Ms. Disha Singh , AOR
Ms. Eliza Barr, Adv.
Ms. Akansha, Adv.
Ms. Anjali Saxena, Adv.
Mr. Govind Sharma, Adv.
Mr. Aaditya Singh Rajawat, Adv.

Mr. Arjun Garg, AOR
Ms. Manisha Ambwani, AOR

Ms. Swati Ghildiyal, AOR
Ms. Neha Singh, Adv.

Mr. Amit Sharma, AOR
Mr. Dipesh Sinha, Adv.
Ms. Pallavi Barua, Adv.
Ms. Aparna Singh, Adv.

Mr. V.V.M.B.N.S. Pattabhiram, D.A.G.
Mr. Aditya Vaibhav Singh Ga, Adv.
Mr. Harmeet Singh Ruprah, AOR
Mr. Kanishk Sharma, Adv.

Mr. Shekhar Raj Sharma, A.A.G.
Mr. Akshay Amritanshu, AOR
Ms. Nidhi Narwal, Adv.
Ms. Srishti Jain, Adv.
Mr. Sarthak Srivastava, Adv.
Mr. Utkarsh Rai, Adv.

Mr. Shuvodeep Roy, AOR

Mr. Gopal Jha, AOR
Mr. Tilak Vij, Adv.
Ms. Shireesha Sharma, Adv.
Mr. Sawan Datta, Adv.
Ms. Priyanshi Goel, Adv.
Ms. Ratna Priya Pradhan, Adv.
Mr. Nimish Arjaria, Adv.
Mr. Atul Kumar, Adv.

Ms. Sansriti Pathak, A.A.G.
Mr. Saurabh Rajpal, Adv.
Ms. Nidhi Jaswal, AOR

Mr. Sudarshan Singh Rawat, AOR
Mr. Madhav Gupta, Adv.
Ms. Nidhi Jain, Adv.
Mr. Sunny Sachin Rawat, Adv.

Ms. Radhika Gautam, AOR

Mr. Aditya Bharat Manubarwala, Adv.
Mrs. Tanishka Grover, Adv.
Mrs. Akriti Aditya Manubarwala, Adv.
Mrs. Shaila Arora, Adv.
Mrs. Charvi Virmani, Adv.
Mrs. Pradnya Sachin Markar, Adv.
Mr. Bharat Thakorlal Manubarwala, AOR

Mr. Samir Ali Khan, AOR
Mr. Kashif Irshad Khan, Adv.
Mr. Pranjal Sharma, Adv.

Mr. Ahanthem Henry, Adv.
Mr. Ahanthem Rohen Singh, Adv.
Mr. Mohan Singh, Adv.
Mr. Aniket Rajput, Adv.
Ms. Khoisnam Nirmala Devi, Adv.
Mr. Yeshu Mehta, Adv.
Mr. Tanay Hegde, Adv.
Mr. Ravi Kumar Bodhani, Adv.
Mr. Kumar Mihir, AOR

Mr. Yashvardhan, Adv.
Mr. Apoorv Shukla, AOR
Ms. Prabhleen A. Shukla, Adv.
Ms. Ilashri Gaur, Adv.

Mr. Nishant Awana, AOR
Ms. Rini Badoni, Adv.
Mr. Suraj Kundu, Adv.
Mr. Amogh Pandey, Adv.

Mr. D. K. Thakur, Adv.
Mr. Rajeev Kumar Gupta, Adv.
Mr. Tavleen Singh, Adv.
Ms. Vallabhi Shukla, Adv.
Mr. Rohit Kumar, Adv.
Mr. Bimlesh Kumar Singh, AOR
Mr. Neeraj Agarwal, Adv.
Mr. Akash Sajan Sapelkar, Adv.

Mr. Samar Vijay Singh, AOR
Ms. Nidhi Narwal, Adv.
Ms. Srishti Jain, Adv.
Ms. Sabarni Som, Adv.
Mr. Aman Dev Sharma, Adv.

Mr. B. Shravanth Shanker, AOR
Ms. Grahita Agarwal, Adv.
Mr. I.V. Sai Nikhil, Adv.
Ms. Prerna Robin, Adv.
Mr. Shivam Kunal, Adv.
Mr. Dandu Laxman, Adv.
Mr. B. Yeshwanth Raj, Adv.
Mr. Shreyas Jayasimha, Adv.
Mr. Tushar Gadia, Adv.
Mr. Suryansh Jamwal, Adv.

Ms. Eliza Barr, Adv.
Ms. Akansha, AOR
Mr. Govind Sharma, Adv.

Mr. Pukhrambam Ramesh Kumar, AOR
Mr. Karun Sharma, Adv.
Ms. Anupama Ngangom, Adv.
Ms. Rajkumari Divyasana, Adv.

Mr. Sunny Choudhary, AOR

Mr. Guntur Pramod Kumar, AOR
Ms. Prerna Singh, Adv.
Mr. Dhruv Yadav, Adv.

Ms. Deepika Nandakumar, AOR
Ms. Kanimozhi J., Adv.

Mr. Gunnam Venkateswara Rao, AOR
Ms. Devyani Mahra, Adv.
Mr. Manoj Kumar Dwivedi, Adv.
Mr. Poli Naidu Vudamala, Adv.

Mr. Shantanu Sagar For Patna High Court, Adv.
Mr. Anil Kumar, Adv.
Mr. Gunjesh Ranjan, Adv.
Mr. Prakash Kumar Mangalam, Adv.
Mr. Manoneet Dwivedi, Adv.
Mr. Abhishek Kumar Gupta, Adv.
Ms. Anshala Verma, Adv.
Mr. Ruchira Gupta, S.C.

Ms. Ishika Gupta, Adv.

Mr. Shantanu Sagar, AOR

Mr. Kunal Mimani, AOR

Ms. Kanika Kalaiyarasan, AOR

Mr. Abhay Kumar, AOR
Mr. Shagun Ruhil, Adv.
Mr. Shreenivash, Adv.
Mr. Karan Chopra, Adv.
Ms. Sakshi Sharma, Adv.

Mr. Sanchit Garga, AOR
Mr. Kunal Rana, Adv.
Mr. Shashwat Jaiswal, Adv.
Ms. Diksha Arora, Adv.
Mr. Bhanu Pratap Singh, Adv.
Mr. Vijender Kumar, Adv.
Ms. Oorja Goel, Adv.
Ms. Ankita Sharma, AOR

Mr. Rushab Aggarwal, Adv.
Mr. Pashupathi Nath Razdan, AOR

Ms. Devina Sehgal, AOR
Mr. Srikanth Varma Mudunuru, Adv.

Ms. Nidhi Mittal, AOR

Mr. Sanjai Kumar Pathak, AOR
Mrs. Shashi Pathak, Adv.
Mr. Arvind Kumar Tripathi, Adv.
Mr. Robin Kumar, Adv.

Mr. Harshad V. Hameed, AOR

Mr. Amit Pai, AOR
Ms. Pankhuri Bhardwaj, Adv.
Ms. Bhavana Duhoon, Adv.
Mr. Abhiyudaya Vats, Adv.
Mr. Shathaayu Patil, Adv.

Mr. Niranjan Sahu, AOR

Mr. Avijit Mani Tripathi, AOR
Mr. Z.H. Isaac Haiding, Adv.
Mr. Daniel Stone Lyngdoh, Adv.
Ms. Marbiang Khongwir, Adv.
Mr. T.K. Nayak, Adv.

Mr. Kunal Vajani, A.A.G.
Mr. Sanchit Garga, AOR

Mr. Amitoj Chadha, Adv.

Ms. Kanika Kalaiyarasan, AOR

Upon hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

1. List the matters with compliance cum periodic reports on 15.10.2026.

2. The Registry to communicate a copy of this order to all concerned forthwith.

(D. NAVEEN)
COURT MASTER (SH)

(ANU BHALLA)
COURT MASTER (NSH)

(The detailed signed order is placed on the file)

MA 01/
18.22
24/9